भारत का बढ़ता रुतबा
एक उभरती हुई शक्ति

पिछले नौ वर्षों में भारत की प्रगति में जबरदस्त बदलाव आया है। भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अभूतपूर्व स्तर हासिल करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। आज, भारत एक विश्व मित्र (वैश्विक मित्र), एक विश्व गुरु (वैश्विक शिक्षक) और एक विश्व वैद्य (वैश्विक चिकित्सक) के रूप में उभरा है।

सुजन चिनॉय

एक पूर्व राजदूत और महानिदेशक, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के लिए थिंक20 चेयर। ईमेल: dg.idsa@nic.in

ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष ने दुनिया को राजनीतिक, वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेदों से भर दिया है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, प्रतिस्पर्धी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत दोहरे विकल्पों से परे एक नई दिशा के लिए लालायित है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर घातक प्रहार किया। कोविड के बाद के पुनर्प्राप्ति चरण में, जिसमें वैश्विक समुदाय को एक साथ आना चाहिए था, इसके बजाय गहरे विभाजन देखे जा रहे हैं। ब्रेटन वुड्स संरचनाओं सहित बहुपक्षीय प्रणाली, परिणाम देने में विफल रही हैं। संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के लिए मदद और आशा दुर्लभ है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, जो भोजन, ईंधन, उर्वरक और विकासात्मक वित्त की उपलब्धता में व्यवधान की बहुआयामी चुनौती का सामना कर रही है।

यह भू-राजनीतिक उथल-पुथल के महत्वपूर्ण मोड़ पर है कि भारत ने जी20 के अपने नेतृत्व, अपने मूल्य-आधारित दृष्टिकोण, वैश्विक सहयोग पर बल देने और सभी के लिए शांति और प्रगति के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से शेष दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। इस वर्ष जी20 की भारत की अध्यक्षता, भारत और दुनिया भर

में कई विरोधियों द्वारा लगातार व्यक्त किए गए संदेह के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), व्यापक-आर्थिक स्थिरता, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढाँचा, जलवायु चुनौती, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत हरित परिवर्तन, और बहुपक्षीय संरचनाओं में सुधार जैसे प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने में एक बड़ी सफलता थी। एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में भारत की छवि, जो पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत से सामने आयी है, महामारी की चरम सीमा पर दुनिया भर के देशों को दिए गए टीकों और स्वास्थ्य देखभाल सहायता के परिणामस्वरूप और भी मजबूत हुई है।

भारतीय नेतृत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत को अब वैश्विक मंच पर पर्यवेक्षक के रूप में नहीं देखा जाता है। यह अब परिणामों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के जी20 आदर्श वाक्य और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित एक उदाहरण, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ (एयू) को जी20 में शामिल करना है, जो भारत की ''किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना'' संबंधी वकालत को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण विकास, जो जी20 संरचना को अधिक प्रतिनिधिक बनाता है, वैश्विक दक्षिण के एक सच्चे मित्र के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में परिलक्षित सकारात्मक परिणाम हाल के वर्षों में मोदी सरकार द्वारा की गई कई पहलों से मेल खाते हैं। महामारी के दौरान वैक्सीन सहायता कार्यक्रम के अलावा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई), और लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे का उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक है। इस सूची में ग्रीन ग्रिड पहल-वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी) को जोड़ा जाना चाहिए, जिसे 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की पहली असेंबली में पीएम मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

मिशन लाइफ और जलवायु संकट

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय अवक्रमण दुनिया की दो सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में उभरी हैं, जिनमें भावी पीढ़ियों के लिए अकल्पनीय प्रतिकूल परिणाम पैदा करने की क्षमता है। यहीं पर भारत ने स्थिति को सुधारने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विस्फोटक व्यापारवाद जो विकसित पश्चिम और संकटग्रस्त वैश्विक दक्षिण के बीच दरार को दर्शाता है, से परे एक अलग रास्ते की ओर संकेत किया है। भारत ने एक नई नैतिक दिशा-निर्देश की पेशकश की है, जिसे पहली बार ग्लासगो में पीएम मोदी ने मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के माध्यम से समझाया था, जो व्यक्तिगत व्यवहार को वैश्विक जलवायु कार्रवाई विमर्श को केंद्र में रखता है।

सतत विकास के लिए जीवन शैली पर जी20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों के रूप में संहिताबद्ध, अब इस मिशन का उद्देश्य स्थायी उपभोग पैटर्न के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल

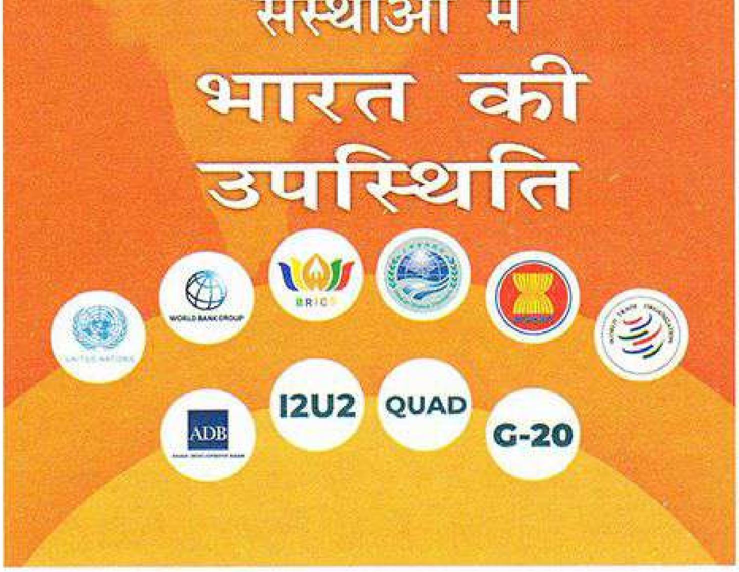

जीवन शैली के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों के एक वैश्विक नेटवर्क का प्रचार करना है। अपनी ओर से, भारत एकमात्र जी20 देश है जिसने अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को 2030 के निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले हासिल कर लिया है। यहां तक कि जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने भी स्वीकार किया कि भारत स्वच्छ ऊर्जा में एक निर्विवाद विश्व नेता है।

पीएम मोदी ने 2030 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है, जिसमें 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना और अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना शामिल है। भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक जलवायु शमन अपने नेताओं की प्रतिबद्धता को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शित करने का वादा करता है। भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत करके अपनी जलवायु कार्रवाई को तेज करने का इरादा व्यक्त किया। यह अद्यतन 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।

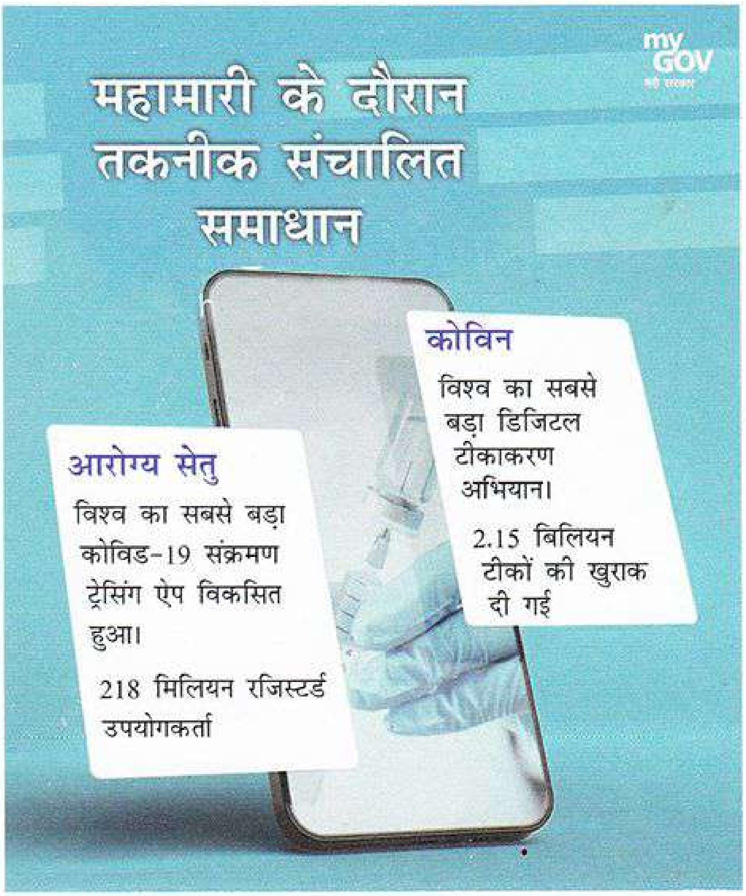

स्वच्छ ऊर्जा

इसी तरह, जून 2022 में जी-7 शिखर सम्मेलन में, पीएम मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "भारत में दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। भारत की विशाल रेलवे प्रणाली इस दशक में नेट शून्य हो जाएगी। हमने समय से नौ साल पहले गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40 प्रतिशत ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है।" प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावों के अलावा, भारत ने यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

भारत और अमेरिका ने मिलकर यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (यूएसआईएससीईपी) को नया रूप दिया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना, उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना और पांच प्रमुख स्तंभों के माध्यम से तकनीकी समाधानों को अपनाना है:

(i) विश्वस्त तेल और गैस स्तंभ
(ii) शक्ति और ऊर्जा दक्षता स्तंभ
(iii) नवीकरणीय ऊर्जा स्तंभ
(iv) सतत विकास स्तंभ, और
(v) उभरते ईंधन और प्रौद्योगिकियाँ।

एक और पहल यूरोपीय संघ और भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (सीईसीपी) है, जिसे 2016 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा जैसे जलवायु-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाकर स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों में अपतटीय पवन ऊर्जा, छत पर सौर पैनल और सौर पार्क, नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण का एकीकरण, स्मार्ट ग्रिड, जैव ईंधन और इमारतों में ऊर्जा दक्षता की गतिविधियाँ शामिल हैं। अक्टूबर 2017 में ईयू-भारत शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान में इस साझेदारी

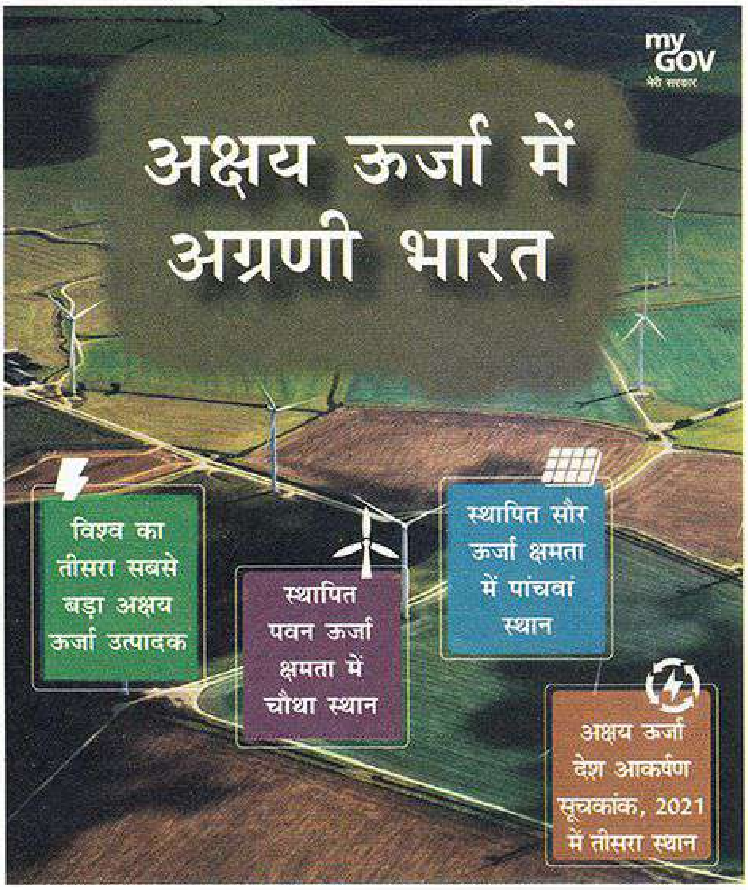

की पुन: पुष्टि की गई और बाद में जुलाई 2020 में ईयू-भारत रणनीतिक साझेदारी: 2025 के लिए एक रोडमैप पर सहमति व्यक्त की गई।

ऊर्जा पर ध्यान न केवल सामान्य प्रकृति का है बल्कि विशिष्ट भी है। भारत हाइड्रोजन में उभरते वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा और देश अंतत: शुद्ध ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। हरित हाइड्रोजन का निर्यात करने और देश भर में विभिन्न स्थानों पर हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए, भारत ऑस्ट्रेलियाई मॉडल का अनुकरण कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि जल्द ही भारत न केवल हरित हाइड्रोजन बल्कि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आपूर्ति शृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाएगा, ताकि चल रहे व्यवधानों के लिए सुरक्षित विकल्प सुनिश्चित किया जा सके। इससे भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में एक बड़ी छलांग मिलेगी।

लचीली आपूर्ति शृंखलाएँ

दिसंबर 2021 में, सरकार ने भारत में चिप विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 10 बिलियन डॉलर की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की। मार्च 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र विकसित करने के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी। अप्रैल 2022 में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला में प्रमुख भागीदारों में से एक भागीदार के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भारत में "एक असाधारण सेमीकंडक्टर डिज़ाइन प्रतिभा पूल है, जो दुनिया के 20 प्रतिशत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियरों को बनाता है।'' इसके अलावा, शीर्ष 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों में से अधिकांश के डिजाइन या अनुसंधान एवं विकास केंद्र हमारे देश में हैं।

ऑस्ट्रेलिया और जापान के सहयोग से शुरू की गई त्रिपक्षीय आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल, एक और आपूर्ति शृंखला संकट का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य चीन से दूर तीन देशों और समान विचारधारा वाले भागीदारों के लिए आपूर्ति शृंखला विविधीकरण का समन्वय और प्रोत्साहन करना है। नई पहल विकसित करने के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल और दुर्लभ पृथ्वी के संबंध में संभावित एकाधिकार और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के व्यापक निहितार्थों की भी जांच जरूर करनी चाहिए, जिनमें से कई हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में तेजी से डिजिटलीकरण हुआ है। दिनांक 1 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री ने भारत को एक सशक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 'डिजिटल इंडिया' की शुरुआत की। तब से, पिछले आठ वर्षों में पूरे भारत में मोबाइल स्वामित्व में भारी वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए इंटरनेट की वहनीयता और पहुंच बढ़ाना तथा देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने से शासन में पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई है। आज, लगभग सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक डिजिटल डैशबोर्ड होता है जो लाभार्थियों के सभी विवरण प्रदान करता है। वर्ष 2021 में, भारत ने 48 बिलियन वास्तविक समय डिजिटल लेनदेन, या वैश्विक कुल का 40 प्रतिशत दर्ज किया। दिलचस्प बात यह है कि यह चीन से लगभग तीन गुना अधिक है और दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं: अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त रीयल टाइम भुगतान मात्रा से सात गुना अधिक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल परिवर्तन किसी से अनदेखा नहीं रहा। दुनिया भर के देशों ने यूआईडीएआई, आधार और एकीकृत भुगतान पोर्टलों के भारतीय मॉडल में रुचि दिखाई है जो

भारत की विशाल आबादी को एक निर्बाध समग्रता से जोड़ते हैं।

योग और आयुर्वेद

भारत पारंपरिक रूप से वैश्विक कल्याण में योगदान देने में उत्कृष्ट रहा है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया, जब इसने लगभग 100 देशों को मुफ्त टीके प्रदान किए और अफगानिस्तान, यूक्रेन और कई अफ्रीकी देशों को खाद्य सहायता और मानवीय सहायता भेजी। भारत ने न केवल टीकों का निर्यात करके बल्कि स्वस्थ रहने की आदतों को बढ़ावा देकर इलाज से भी अधिक रोकथाम का समर्थन किया है। रोग और चिकित्सा की पश्चिमी धारणा पूर्वी प्रारूप से भिन्न है। भारत चिकित्सा के हिस्से के रूप में भोजन और योग जैसी पारंपरिक प्रथाओं में विश्वास करता है जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

2014 में अपने यूएनजीए भाषण में, पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखते हुए इसे बढ़ावा देने की मांग की थी। योग की महान भारतीय विरासत को दुनिया के साथ साझा करना मानव जाति के लिए मोदी का व्यक्तिगत उपहार था। आज, दुनिया भर के देश वैचारिक और धार्मिक बाधाओं से परे, भारत की प्राचीन सभ्यता द्वारा दी गई समग्र स्वास्थ्य प्रथाओं में योग्यता देखते हैं। जब तक भारत ने इस तरह की अग्रणी पहल के माध्यम से अपनी विरासत को साझा करने की पेशकश नहीं की, तब तक योग का अभ्यास विदेशों में महंगे स्टूडियो में किया जाता था जो अजीब व्याख्याओं के अधीन होता था, यहां तक कि खेल प्रतियोगिताओं का हिस्सा भी बनाया जाता था। इस पहल ने योग के सच्चे अभ्यास को उसके शुद्धतम रूप में पुनर्जीवित किया, जिससे यह दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध हुआ।

कोविड के दौरान, सरकार ने प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों या सरल घरेलू उपचार को बढ़ावा दिया। यह एलोपैथिक चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक है। भारत ने विभिन्न देशों की मदद के लिए दवाओं और अन्य उपकरणों का निर्यात किया और हिंद महासागर क्षेत्र में पहला रेसपोंडेन्ट (प्रतिवादी) बन गया। वैक्सीन मैत्री ने 101 देशों में वैक्सीन पहुंचाने में मदद की। इसके अलावा, भारत ने अन्य विकासशील देशों को कोविन और आरोग्य सेतु जैसे ओपन-सोर्स ऐप प्रदान किए हैं। सरकार ने इन्हें डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में घोषित किया, जिसका उपयोग 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए किया है।

मिलेट्स यानी श्रीअन्न या मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष

खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर, घरेलू और वैश्विक पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलेट्स की क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव दिया कि 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (प्लवड-2023) घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला और 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने आधिकारिक तौर पर 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। यह अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक प्राथमिक खाद्य फसल है, जहां पारंपरिक खाद्य फसलें सीमित वर्षा और खराब मिट्टी की गुणवत्ता के कारण पनपने के लिए संघर्ष करती हैं। मिलेट्स प्रमुख अनाज फसलों की तुलना में बेहतर पोषण तत्वों का दावा करता है, जो खाद्य सुरक्षा और आहार स्वास्थ्य में योगदान देता है। वे विशेष रूप से सूखे और चरम मौसम की स्थिति के प्रति लचीले होते हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं।

मधुमेह जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और परिष्कृत आहार के प्रचलन के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, आधुनिक उपभोक्ता धीरे-धीरे गेहूं और चावल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के व्यवहार्य विकल्प के रूप में ग्लूटेन-मुक्त मिलेट्स की ओर रुख कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने इस बदलाव को तेज कर दिया, शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादियों ने अपने पोषण सेवन को बढ़ावा देने और अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए मिलेट्स को अपना लिया। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान मिलेट्स के स्वास्थ्य संबंधी लाभों को भारी बढ़ावा मिला। भारत में आयोजित सैकड़ों जी20 कार्यक्रमों में हजारों विदेशी और भारतीय प्रतिभागियों को मिलेट्स से बने कई व्यंजन परोसे गए। भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के थिंक20 अध्यक्ष के रूप में, लेखक को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि थिंक20 सहभागिता समूह द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में मिलेट्स को प्रमुखता से दिखाया गया है।

निष्कर्ष

पिछले नौ वर्षों में भारत की प्रगति में जबरदस्त बदलाव आया है। भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अभूतपूर्व स्तरों को हासिल करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तो वह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति होगा। यह, सभी भारतीय लोगों, विशेषकर युवाओं की ओर से इस सपने को हासिल करेगा। भारत गौरव के शिखर पर पहुंचेगा क्योंकि वह आज विविध क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने और व्यापक रूप से कल्याण करने में योगदान देने को इच्छुक है। आज, व्यापार, सैन्य या वैचारिक टकराव में उलझे कई अन्य लोगों के विपरीत, भारत एक विश्व मित्र (वैश्विक मित्र), एक विश्व गुरु (वैश्विक शिक्षक) और एक विश्व वैद्य (वैश्विक चिकित्सक) के रूप में उभरा है। ❑

(व्यक्त विचार निजी हैं)